

# अमृत कलश टाइम्स

वर्ष : 18  
अंक : 30

प्रयागराज मंगलवार 15 अक्टूबर 2024

पृष्ठ:- 4, मूल्य:- एक रुपया

## सीएम बोले, माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं, उपद्रवियों की होगी पहचान

बहराइच, (एजेंसी)। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा

हुई। इस हिंसा में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। कुछ युवक इस घटना से घायल हुए हैं। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहराइच के महसूसी में माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के महसूसी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आदेश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि प्रतिमा विसर्जन का कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहना चाहिए और धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय पर प्रतिमा विसर्जन कराया जाए। उन्होंने जनता को सुरक्षा की गारंटी देते हुए प्रशासन व पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल पर मौजूदगी सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिनकी लापरवाही से इस प्रकार की घटना घटित हुई, उनकी पहचान की जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उल्लेखनीय है कि बहराइच के महाराजगंज बाजार में कुछ लोगों द्वारा मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी करने पर दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए थे। गुरसाईं भीड़ ने बाजार में तोड़फोड़ की। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है।

## हिंसा फैलाने वालों के विरुद्ध हो सख्त कार्रवाई: प्रियंका गांधी

नयी दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्वा ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा की वारदात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा

है कि कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। श्रीमती वाड्वा ने कहा कि हिंसा करने का अधिकार किसी को नहीं है लेकिन प्रशासन को भी इस मामले में सक्रिय बनने और जनता को विश्वास में लेकर दोषियों के विरुद्ध सख्ती से काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "बहराइच, उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एवं राज्य प्रशासन से अपील करती हूँ कि त्वरित एक्शन लेते हुए, जनता को विश्वास में लें और हिंसा रोकें। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।" श्रीमती वाड्वा ने कहा, "जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि कृपया कानून अपने हाथ में न लें और शांति बनाए रखें।"

## प्रदेश की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी साजिश सफल नहीं होगी: केशव

बहराइच, (एजेंसी)। बहराइच जिले के हरदी क्षेत्र के महाराजगंज बाजार

में रविवार को देवी दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन जुलूस के दौरान गोलीबारी और पथराव हो गया जिसमें एक युवक की मौत को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मोर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। दंगाइयों को संरक्षण देने वाले एक बार फिर सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन हमें सतर्क और साजग रहना होगा। प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा दी जाएगी और पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा। सभी नागरिकों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील करता हूँ। बड योगी बोले- माहौल खराब करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए लखनऊ में जारी बयान में कहा कि माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

## 'मामला पहले ही बंद हो चुका है'

● बुलडोजर एक्शन में नई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

नयी दिल्ली, (एजेंसी)। याचिका में तर्क दिया गया कि जहां भी बुलडोजर कार्रवाई के कारण क्षति होती है, पीड़ितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए और इसमें शामिल अधिकारियों के साथ-साथ प्रभावित लोगों के नाम भी सार्वजनिक किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा लोगों के घर गिराए जाने की स्थिति में लोगों को मुआवजा देने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामला पहले ही बंद कर दिया गया है और याचिकाकर्ता से याचिका वापस लेने को कहा, जो बाद में



किया गया। याचिका में तर्क दिया गया कि जहां भी बुलडोजर कार्रवाई के कारण क्षति होती है, पीड़ितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए और इसमें शामिल अधिकारियों के साथ-साथ प्रभावित लोगों के नाम भी सार्वजनिक किए जाने चाहिए। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा, मामले पहले ही फैसले के लिए बंद हो चुका है। या तो आप इसे वापस लें लें, या हम इसे खारिज कर देंगे। इसके बाद वकील याचिका वापस लेने पर सहमत हो गए। 1 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने अर्द्ध निर्माण का हवाला देते हुए कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों से जुड़ी संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

# बहराइच में हिंसा

आगजनी और तोड़फोड़, उपद्रवियों ने घर भी फूँके, इंटरनेट बंद



## पहले गाली गलौज और फिर पथराव

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महसूसी तहसील की प्रतिमा शांति पूर्वक विसर्जन के लिए जा रही थी। महाराजगंज कस्बे में पहुंचने पर कस्बा निवासी सोनार अब्दुल हमीद अपने बेटे सब्बू, सरफराज व फहीम के साथ मौके पर पहुंचे और गाली गलौज शुरू कर दी। प्रतिमा के साथ चल रहे लोगों ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया गया। इसके बाद विसर्जन रोक समिति सदस्यों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि इस दौरान हमीद व उनके साथ मौजूद हजारों की भीड़ मौके पर पहुंची और उपद्रव शुरू कर दिया।

आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। अस्पताल के अलावा दुकानों और वाहनों में भी आग लगाई गई। यूपी के सीएम योगी ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ताजा हालात पर रिपोर्ट मांगी है। अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए कहा है। इससे पहले, बहराइच सांप्रदायिक हिंसा में जान गंवाने वाले रामगोपाल मिश्रा का पोस्टमार्टम सुबह सात बजे पूरा हुआ। इसके बाद शव उनके घर की तरफ रवाना किया गया था। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। महाराजगंज और महसूसी इलाके के निजी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। मुख्य आरोपी सलमान सहित 25 गिरफ्तार बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा में देर रात मुख्य आरोपी सलमान समेत कई लोगों पर एफआईआर की गई। सूत्रों के अनुसार 20 से 25 लोगों के हिरासत में लेने की खबरें हैं।

बहराइच, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल ने बड़ा रूप ले लिया है। सोमवार सुबह एक बार फिर से बहराइच में आगजनी और तोड़फोड़ की गई। कई दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की गई। बाइक के शोरूम और एक अस्पताल में आग

लगा दी गई है। वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। दवाइयों को जला दिया गया है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हिंसा बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक, चंदपैया और कबडियापुरवा गांव में भी आगजनी हुई है। कई घर जलाए गए हैं। वाहनों को भी आग के हवाले

कर दिया गया है। तीस उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर एसीएस होम एवं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर पहुंचे हैं। छह कंपनी पीएसई बहराइच भेजी गई हैं। युवक की मौत से भड़का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शन और हिंसक

होता जा रहा है। बाइक के शोरूम में आग लगा दी गई है। कारों को भी फूँका गया है। लोग लाठी-डंडे लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। उधर, परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। हालांकि पुलिस ने मृतक के परिजनों को समझाया है। लेकिन

## पीएम मोदी से मिलीं सीएम आतिशी

● सीएम बनने के बाद पहली भेंट, सामने आई तस्वीर

नयी दिल्ली, (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी ने पिछले महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वह राष्ट्रीय राजधानी में इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाली सभी तीन महिलाओं में सबसे कम उम्र की हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिल्ली का मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री के साथ यह उनकी पहली मुलाकात थी। बैठक का एजेंडा अभी साफ नहीं हुआ है। उत्पाद शुल्क घोटाला मामले में जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद पर आसानी होने वाली 17वीं महिला भी बन गयी हैं।



वैसे वरिष्ठ आप नेता आतिशी का मुख्यमंत्री के रूप में संक्षिप्त कार्यकाल होगा क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव फरवरी में होने वाले हैं। पहली बार की विधायक आतिशी पार्टी का एक बड़ी चेहरा हैं और उन्होंने आबकारी नीति मामले के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल में रहने के दौरान आप का कामकाज संभाला।

## चिराग पासवान को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी

नयी दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री एवं हाजीपुर से सांसद, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान का सुरक्षा कवर बढ़ाने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने श्री पासवान को जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अब श्री पासवान की सुरक्षा में 33 सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 33 जवान 24 घंटे उनकी सुरक्षा में रहेंगे। यह निर्णय श्री पासवान पर खतरे की बढ़ती आशंका की रिपोर्ट को देखते हुए लिया गया है, हालांकि अभी सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा बढ़ाने का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है।

## जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ

जम्मू, (एजेंसी)। हम आपको याद दिला दें कि हाल में संपन्न हुए जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें गठबंधन का नेता चुना गया है। जम्मू-कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है जिससे केंद्र शासित प्रदेश में नयी सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाया जाने का विभिन्न दलों ने स्वागत किया है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा गया है, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 और 239ए के साथ पठित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में 31 अक्टूबर 2019 का आदेश, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले निरस्त किया जाता है।"



## सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक

कहा- बुलडोजर का महिमामंडन बंद हो



लिए बंद हो चुका है। या तो आप इसे वापस लें लें, या हम इसे खारिज कर देंगे। इसके बाद वकील याचिका वापस लेने पर सहमत हो गए। 1 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने अर्द्ध निर्माण का हवाला देते हुए कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों से जुड़ी संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

## 24 घंटे में इस दो टुके गैंगस्टर के नेटवर्क को खत्म कर दूंगा: पप्पू यादव

पटना, (एजेंसी)। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और तीन बार के विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद राजनीति गरमा गई है। विपक्षी पार्टियां शिंदे सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि अगर इतने बड़े नेता की हत्या हो सकती है, तो राज्य में आम जनता की सुरक्षा कितनी सुनिश्चित है। इस बीच, बिहार के निर्दलीय सांसद करने के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।



## खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल से बढ़ोतरी

● सितंबर में थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 1.84 फीसदी पर

नयी दिल्ली, (एजेंसी)। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सितंबर, 2024 में मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, खाद्य उत्पादों, अन्य विनिर्माण, मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों के निर्माण, मशीनरी और उपकरणों के निर्माण आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है। सन्नियों और अन्य खाद्य पदार्थों के महंगे होने से थोक मूल्य मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर 1.84 फीसदी हो गई। अगस्त में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति 1.31 फीसदी थी। पिछले साल सितंबर में यह 0.07 फीसदी घटी थी। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, खाद्य मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर



11.53 फीसदी हो गई, जबकि अगस्त में यह 3.11 फीसदी थी। इसकी वजह क्या? इसकी वजह सन्नियों की मुद्रास्फीति रही, जो सितंबर में 48.73 फीसदी बढ़ी थी। अगस्त में यह 10.01 फीसदी घट गई थी। आलू की मुद्रास्फीति सितंबर में 78.13 और प्याज की 78.82 प्रतिशत पर उच्च स्तर पर बनी रही। ईंधन और बिजली श्रेणी में सितंबर में 4.05 फीसदी की अपस्फीति देखी गई, जबकि अगस्त में 0.67 प्रतिशत की अपस्फीति हुई थी। मंत्रालय ने क्या कहा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सितंबर, 2024 में मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, खाद्य उत्पादों, अन्य विनिर्माण, मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों के निर्माण, मशीनरी और उपकरणों के निर्माण आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है।

## सम्पादकीय

### महंगाई की मार और त्यौहार

महंगाई की मार ने त्योहारी रंग फीका कर दिया है। केवल लग्जरी आइटम या फिर जूते, कपड़े, ड्राइंगरूम व बेडरूम तथा रसोई का समान ही महंगा नहीं है। बाजार में सबसे बुरा हाल तो फल व सब्जियों का है। नवरात्र व्रत शुक्रवार को निपटे हैं। इन व्रत में आमतौर पर व्रत रखने वाले फलाहार लेते हैं, लेकिन फलों की कीमतों में उछाल के चलते बाजार में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फलों के दाम तो पूछते,लेकिन लेने के बजाए आगे बढ़ जाते। इस वक्त फल ही नहीं, सब्जियां भी रसोई का बजट बिगाड़ रही हैं। टमाटर 100 और 120 रुपये प्रतिकिलो जा पहुंचा है। जबकि सेब का रेट 100 रुपये प्रति किलो है। इस बार व्रत में अच्छा केला 100 रुपये दर्जन तक बिका है। फल मंडी के आदती भी मान रहे हैं कि इस बार महंगाई सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने पर आमादा है।खाद्य तेल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इसमें सरसों के तेल से लेकर पाम आयल, सूरजमुखी, नारियल, मूंगफली और अन्य तेल भी शामिल हैं। सामने पेरा गया सरसों के तेल की कीमत 140 रुपये प्रति लीटर से 160 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई हैं। कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे देश में इनकी कमजोर फसल का होना और खाद्य तेलों की लगातार विदेश आयात पर निर्भरता बढ़ने को बताया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। वैसे महंगाई से सम्पूर्ण विश्व प्रभावित है। लेकिन भारत में जमाखोरों और खुदरा बाजार सरकार के नियंत्रण से बाहर होने के कारण स्थिति दिन पद दिन बदतर हुई है। असमान आय के मामले में भारत में महंगाई चरम पर दिखाई पड़ती है। क्योंकि आज भी भारत में आधी से अधिक आबादी महीने में दस हजार से अन्दर की आय में तथा 25 प्रतिशत आबादी पाँच हजार रुपये महीने की आय पर निर्भर है। इन दिनों ईरान और इस्त्राएल सहित पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष तथा रूस-यूक्रेन युद्ध के विस्तारित होने से भारत के समक्ष कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, शेयर बाजार में गिरावट, माल ढुलाई की लागत बढ़ने, खाद्य वस्तुओं की महंगाई, भारत से चाय, मशीनरी, इस्पात, रत्न, आभूषण तथा फुटवियर जैसे क्षेत्रों में निर्यात आदेशों में कमी, निर्यात के लिए बीमा लागत में वृद्धि तथा इस्त्राएल और ईरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार में कमी के रूप में दिखाई दे रही हैं। वैश्विक शेयर बाजार के साथ-साथ भारत के शेयर बाजार पर भी असर पड़ना शुरू हुआ है। पश्चिम एशिया संकट और चीन से सरकारी प्रोत्साहन के दम पर बाजार चढ़ने के मद्देनजर भारत के शेयर बाजार में कुछ विदेशी निवेशकों द्वारा जोखिम वाली संपत्तियां बेची जा रही हैं और वे अपना कुछ निवेश निकाल रहे हैं। स्थिति यह है कि सेंसेक्स और निफ्टी के लिए अक्टूबर, 2024 का पहला सप्ताह 4.5 फीसदी के नुकसान के साथ दो साल की सबसे बड़ी गिरावट का सप्ताह रहा है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की खरीद का भी रुख कर रहे हैं। इससे भारत में भी सोने की खपत और सोने की कीमत बढ़ने लगी है। ऐसे वक्त में जब भारतीय बाजार त्योहार की रंगत में रंगने लगे हैं और कारोबारियों को बेहतर कारोबार की उम्मीद है, भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई को लेकर फिर्कमंद है। उसे चिंता है कि महंगाई बढ़ी तो त्योहार की रौनक प्रभावित हो सकती है। इसीलिए मौद्रिक नीति की घोषणा करते वक्त केंद्रीय बैंक ने रेपो दर को यथावत बनाये रखा है। बहरहाल, ये आने वाला वक्त बताएगा कि रिजर्व बैंक किस हद तक महंगाई पर नियंत्रण रखने में सफल हो पाता है। दरअसल, केंद्रीय बैंक का लक्ष्य है कि महंगाई की दर को चार फीसदी से नीचे रखी जाए। चिंता जतायी जा रही है कि आने वाले दो वर्ष में यह दर चार फीसदी से ऊपर रह सकती है। जब दो साल पहले खुदरा महंगाई की दर सात फीसदी के करीब पहुंच गई थी तो केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक उपायों से महंगाई पर काबू पाने का प्रयास किया। बैंक ने धीरे-धीरे रेपो दर में वृद्धि की थी। फिलहाल छह बार की बढ़ोतरी से फिलहाल इस दर में करीब ढाई फीसदी की वृद्धि हो चुकी है। अब महंगाई बढ़ने की फिर्क में केंद्रीय बैंक ने दसवीं बार रेपो दर को यथावत रखा है। जो फिलहाल साढ़े छह फीसदी है। दरअसल, बैंक का आकलन है कि आने वाले दो वर्षों में महंगाई की दर चार फीसदी से ऊपर रह सकती है। केंद्रीय बैंक यदि उद्यमियों के दबाव के बावजूद बैंक दरों में कमी नहीं कर रहा है तो उसकी वजह महंगाई की फिर्क में थमे कदम हैं। बैंक का आकलन है कि यदि हम महंगाई की दर को अपने लक्ष्य चार फीसदी से कम लाने में कामयाब हो जाते हैं तो देश की विकास दर के ऊंचे लक्ष्य हासिल किये जा सकते हैं। इतना ही नहीं, विकास दर दो अंकों का आंकड़ा छू सकती है।यह एक हकीकत है कि जहां दुनिया के अन्य विकसित देश मंदी के संकट से जूझ रहे हैं, भारत मंदी के दुष्प्रभाव से अर्थव्यवस्था को बचा पाया है। निस्संदेह, हमारी मौद्रिक नीतियां आर्थिकी को स्थायित्व प्रदान करने में किसी हद तक सफल रही हैं। यही वजह है कि संवेदनशील आर्थिकी के वैश्विक परिदृश्य में केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीतियों में बदलाव से परहेज किया है। निस्संदेह, भारत इस समय दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। इस स्थिति को बनाए रखने के लिये खासी सावधानी भी जरूरी है। लेकिन ऊंची रेपो दर का नुकसान देश के उन उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है, जो घर-वाहन लोन की ईएमआई कम होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि, देश के बुजुर्गों को बचत खाते में अधिक ब्याज मिलने से लाभ जरूर हो रहा है। लेकिन महंगाई का प्रभाव तो समाज के हर वर्ग पर पड़ रहा है। वहीं थोक व फुटकर की महंगाई के आंकड़े मले ही इसके कम होने की बात कर रहे हों, लेकिन व्यवहार में फल-सब्जी व खाद्य पदार्थों की महंगाई उपभोक्ताओं के बजट को प्रभावित कर रही है। दूसरी ओर कर्ज लेने वाले लोगों को बढ़ी किस्तें भी परेशान कर रही हैं। कारोबारी और कामकाजी लोग काफी समय से आस लगाए बैठे थे कि यदि रिजर्व बैंक रेपो दरों में कुछ कमी करता है तो ऋण सस्ते होने से उनके कर्ज की किस्त कुछ हल्की हो जाएगी। लेकिन महंगाई की चिंता कर रहा केंद्रीय बैंक ऐसे किसी कदम को उठाने से परहेज कर रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि महंगाई दर में कमी के दावों का अडसस आम आदमी को भी होना चाहिए। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि महंगाई के आंकड़ों पर काबू पाने का वास्तविक लाभ आम उपभोक्ता को कैसे और कब मिलेगा। कोशिश यह होनी चाहिए कि त्योहार के मौसम में आम आदमी को दैनिक उपभोग की वस्तुएं मसलन खाद्यान्न, सब्जी-फल, डेरी उत्पाद व खाद्य तेल पाकिज दामों में मिले। तभी महंगाई पर नियंत्रण के सरकारी दावे सिरे चढ़ सकेंगे।

## भारी पड़ सकता है काम का तनाव, बढ़ रहे हैं ऑक्यूपेशनल डेथ के मामले

○ भारत में हाल के दिनों में ऑफिस और फक्ट्रियों के कर्मचारियों पर काम के दबाव के कारण मौत के कई मामले सामने आए हैं। रिसर्च में खुलासा हुआ है कि ज्यादातर युवाओं की मौतें वर्क लोड की वजह से हुई हैं, इसे डॉक्टर ऑक्यूपेशनल डेथ कहते हैं। ये मौतें काम करते-करते हुई हैं। इनको वर्क रिलेटेड डेथ ट्रीट किया जाना चाहिए इनको मुआवजा मिलनी चाहिए।

शशांक द्विवेदी पिछले दिनों लखनऊ में एचडीएफसी बैंक में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी (45 वर्षीय सदफ फातिमा) की वर्क प्रेशर के चलते जान चली गई। इसके पहले पुणे में इर्नस्ट एंड यंगर में काम करने वाली एक युवा सीए 26 साल की ऐना सेबेस्टियन पेरायिल की वर्क प्रेशर के चलते मौत हो गई थी। इन दोनों ही घटनाओं ने एक बार फिर से भारत में वर्किंग आवर और वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर बहस छेड़ दी है। सिर्फ 4 महीने की नौकरी में पुणे की ऐना सेबेस्टियन पर काम का इतना बोझ पड़ गया कि उसकी जान चली गई। वहीं, एचडीएफसी बैंक में काम करने वाली फातिमा कुर्सी पर बैठ-बैठे गिरी तो कभी नहीं उठी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में ऑक्यूपेशनल डेथ के आंकड़े आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे। ऐना और फातिमा की मौत के बाद देश में वर्क प्रेशर को लेकर बहस और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों के साथ-साथ बड़े-बड़े डॉक्टरों ने भी सरकार को चेताया है। डॉक्टरों की मानें तो भारत में ओवरवर्क का ट्रेंड बेहद कॉमन है।

भारत में हाल के दिनों में ऑफिस और फक्ट्रियों के कर्मचारियों पर काम के दबाव के कारण मौत के कई मामले सामने आए हैं। रिसर्च में खुलासा हुआ है कि ज्यादातर युवाओं की मौतें वर्क लोड की वजह से हुई हैं, इसे डॉक्टर ऑक्यूपेशनल डेथ कहते हैं। ये मौतें काम करते-करते हुई हैं। इनको वर्क रिलेटेड डेथ ट्रीट किया जाना चाहिए इनको मुआवजा मिलनी चाहिए। आने वाले दिनों में भारत विकसित देश बनेगा तो कंपनियां और फैक्ट्रियों में इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी। इसलिए भारत सरकार को इसके लिए पुर्तुगैल ही कॉन्सुल लाना चाहिए। जापान में पहली ऑक्यूपेशनल डेथ जापान में इस तरह की पहली मौत हुई थी, साल 1969 जापान में एक 29 साल का लड़का न्यूज पेपर के शिपिंग डिपार्टमेंट में काम करते-करते मर गया था। उस लड़के के मरने के बाद उसकी पत्नी ने कंपनी से मुआवजा मांगा। कंपनी ने मुआवजा नहीं दिया तो इसको लेकर एसोसिएशन बना। ६

जापान में इस तरह की पहली मौत हुई थी, साल 1969 जापान में एक 29 साल का लड़का न्यूज पेपर के शिपिंग डिपार्टमेंट में काम करते-करते मर गया था। उस लड़के के मरने के बाद उसकी पत्नी ने कंपनी से मुआवजा मांगा। कंपनी ने मुआवजा नहीं दिया तो इसको लेकर एसोसिएशन बना। ६



पिरे-धीरे कई और लोग भी सामने आए, इसके बाद यह मांग पश्चिम के देशों में भी उठने लगी। इसके बाद एक डेथ ज्यूटू ओवर वर्क एसोसिएशन बना। बाद में डब्ल्यूएचओ ने भी माना कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से दुनिया में 60 लाख से ज्यादा लोग हर साल मरते हैं। यहां तक डेथ ज्यू टू ओवर वर्क में कोई शक्य सुसाइड करता है तो भी उसके परिवारवालों को अब जापान में मुआवजा मिलता है।

साल 2014 में जापान की सरकार एक एक्टलेकर आई, जिसे करोशी एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के तहत वर्क रिलेटेड डेथ ऑक्यूपेशनल डेथ को लेकर कई सारी गाइडलाइंस हैं, जिसे यहां की कंपनियां फॉलो करती हैं। जैसे साल 2018 के बाद जापान ने ओवरटाइम घंटों को सीमित कर दिया। एक वर्कर महीने में 45 घंटे सेज्यादा और साल में 360 घंटे तक ही ओवरटाइम कर सकता है।



भारत में वैसे तो वर्किंग आवर 8 से 9 घंटे का होता है। इस तरह लोग हर हफ्ते 45 से 48 घंटे काम करते हैं। हालांकि, कुछ कंपनियों में लोगों को वर्किंग आवर के बाद भी काम करना पड़ता है। इसकी वजह से ना सिर्फ उनकी शारीरिक स्थिति पर असर पड़ता है, बल्कि काम के दबाव शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों के साथ-साथ बड़े-बड़े डॉक्टरों ने भी सरकार को चेताया है। डॉक्टरों की मानें तो भारत में ओवरवर्क का ट्रेंड बेहद कॉमन है।

इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रशांत महासागर में स्थित वनातू नाम के देश में सबसे कम घंटे तक लोग काम करते हैं। रिपोर्ट तैयार करने के लिए जितने भी देशों में सर्वे किया गया है, उसमें वनातू में सबसे कम वर्किंग ऑवर देखा गया है। यहां एक कर्मचारी हर हफ्ते सिर्फ 24.7 घंटे काम करता है। वनातू की सिर्फ 4 फीसदी आबादी ही हफ्ते में 49 घंटे या उससे ज्यादा काम करती है।

वनातू के बाद दूसरे नंबर पर प्रशांत महासागर में ही मौजूद एक और देश है, जिसका नाम किरिबाती है। यहां पर एक कर्मचारी हर हफ्ते औसतन 27.3 घंटे काम करता है। हैरानी की बात ये है कि भारत सबसे कम वर्किंग आवर वाले देशों में टॉप 20 में भी शामिल नहीं है। भारत की इसको लेकर एसोसिएशन बना। ६

भारत में जितनी भी कंपनियां हैं या फैक्ट्री हैं, सभी श्रम संसाधन मंत्रालय के अंदर आती हैं, खासकर आईटी और मीडिया कंपनियों में डबल वर्क करने पर ज्यादा मौतें हो रही हैं। ये कंपनियां घर में भी डबल वर्क लेती है, जबकि, लेबर मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है कि डिसकनेक्ट की घोषणा की थी इसका साफ मतलब है कि ऑफिस के घंटे पूरे हो जाने के बाद प्रोफेशनल्स के लिए बाँस की कॉल रिसीव करना जरूरी नहीं माना जाएगा।वह चाहें तो उस कॉल को इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा कई जगहों पर होता है। इससे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में लिमिट तय करना आसान हो जाता है। काम और निजी जीवन के बीच स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें, ऑफिस और पर्सनल लाइफ में अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करें।घर और घंटे सेज्यादा और साल में 360 घंटे तक ही ओवरटाइम कर सकता है।

भारत में जितनी भी कंपनियां हैं या फैक्ट्री हैं, सभी श्रम संसाधन मंत्रालय के अंदर आती हैं, खासकर आईटी और मीडिया कंपनियों में डबल वर्क करने पर ज्यादा मौतें हो रही हैं। ये कंपनियां घर में भी डबल वर्क लेती है, जबकि, लेबर मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है कि डिसकनेक्ट की घोषणा की थी इसका साफ मतलब है कि ऑफिस के घंटे पूरे हो जाने के बाद प्रोफेशनल्स के लिए बाँस की कॉल रिसीव करना जरूरी नहीं माना जाएगा।वह चाहें तो उस कॉल को इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा कई जगहों पर होता है। इससे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में लिमिट तय करना आसान हो जाता है। काम और निजी जीवन के बीच स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें, ऑफिस और पर्सनल लाइफ में अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करें।घर और घंटे सेज्यादा और साल में 360 घंटे तक ही ओवरटाइम कर सकता है।

भारत में वैसे तो वर्किंग आवर 8 से 9 घंटे का होता है। इस तरह लोग हर हफ्ते 45 से 48 घंटे काम करते हैं। हालांकि, कुछ कंपनियों में लोगों को वर्किंग आवर के बाद भी काम करना पड़ता है। इसकी वजह से ना सिर्फ उनकी शारीरिक स्थिति पर असर पड़ता है, बल्कि काम के दबाव शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों के साथ-साथ बड़े-बड़े डॉक्टरों ने भी सरकार को चेताया है। डॉक्टरों की मानें तो भारत में ओवरवर्क का ट्रेंड बेहद कॉमन है।

इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रशांत महासागर में स्थित वनातू नाम के देश में सबसे कम घंटे तक लोग काम करते हैं। रिपोर्ट तैयार करने के लिए जितने भी देशों में सर्वे किया गया है, उसमें वनातू में सबसे कम वर्किंग ऑवर देखा गया है। यहां एक कर्मचारी हर हफ्ते सिर्फ 24.7 घंटे काम करता है। वनातू की सिर्फ 4 फीसदी आबादी ही हफ्ते में 49 घंटे या उससे ज्यादा काम करती है।

वनातू के बाद दूसरे नंबर पर प्रशांत महासागर में ही मौजूद एक और देश है, जिसका नाम किरिबाती है। यहां पर एक कर्मचारी हर हफ्ते औसतन 27.3 घंटे काम करता है। हैरानी की बात ये है कि भारत सबसे कम वर्किंग आवर वाले देशों में टॉप 20 में भी शामिल नहीं है। भारत की इसको लेकर एसोसिएशन बना। ६

भारत में जितनी भी कंपनियां हैं या फैक्ट्री हैं, सभी श्रम संसाधन मंत्रालय के अंदर आती हैं, खासकर आईटी और मीडिया कंपनियों में डबल वर्क करने पर ज्यादा मौतें हो रही हैं। ये कंपनियां घर में भी डबल वर्क लेती है, जबकि, लेबर मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है कि डिसकनेक्ट की घोषणा की थी इसका साफ मतलब है कि ऑफिस के घंटे पूरे हो जाने के बाद प्रोफेशनल्स के लिए बाँस की कॉल रिसीव करना जरूरी नहीं माना जाएगा।वह चाहें तो उस कॉल को इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा कई जगहों पर होता है। इससे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में लिमिट तय करना आसान हो जाता है। काम और निजी जीवन के बीच स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें, ऑफिस और पर्सनल लाइफ में अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करें।घर और घंटे सेज्यादा और साल में 360 घंटे तक ही ओवरटाइम कर सकता है।

भारत में जितनी भी कंपनियां हैं या फैक्ट्री हैं, सभी श्रम संसाधन मंत्रालय के अंदर आती हैं, खासकर आईटी और मीडिया कंपनियों में डबल वर्क करने पर ज्यादा मौतें हो रही हैं। ये कंपनियां घर में भी डबल वर्क लेती है, जबकि, लेबर मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है कि डिसकनेक्ट की घोषणा की थी इसका साफ मतलब है कि ऑफिस के घंटे पूरे हो जाने के बाद प्रोफेशनल्स के लिए बाँस की कॉल रिसीव करना जरूरी नहीं माना जाएगा।वह चाहें तो उस कॉल को इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा कई जगहों पर होता है। इससे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में लिमिट तय करना आसान हो जाता है। काम और निजी जीवन के बीच स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें, ऑफिस और पर्सनल लाइफ में अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करें।घर और घंटे सेज्यादा और साल में 360 घंटे तक ही ओवरटाइम कर सकता है।

भारत में वैसे तो वर्किंग आवर 8 से 9 घंटे का होता है। इस तरह लोग हर हफ्ते 45 से 48 घंटे काम करते हैं। हालांकि, कुछ कंपनियों में लोगों को वर्किंग आवर के बाद भी काम करना पड़ता है। इसकी वजह से ना सिर्फ उनकी शारीरिक स्थिति पर असर पड़ता है, बल्कि काम के दबाव शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों के साथ-साथ बड़े-बड़े डॉक्टरों ने भी सरकार को चेताया है। डॉक्टरों की मानें तो भारत में ओवरवर्क का ट्रेंड बेहद कॉमन है।

भारत में वैसे तो वर्किंग आवर 8 से 9 घंटे का होता है। इस तरह लोग हर हफ्ते 45 से 48 घंटे काम करते हैं। हालांकि, कुछ कंपनियों में लोगों को वर्किंग आवर के बाद भी काम करना पड़ता है। इसकी वजह से ना सिर्फ उनकी शारीरिक स्थिति पर असर पड़ता है, बल्कि काम के दबाव शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों के साथ-साथ बड़े-बड़े डॉक्टरों ने भी सरकार को चेताया है। डॉक्टरों की मानें तो भारत में ओवरवर्क का ट्रेंड बेहद कॉमन है।

भारत में वैसे तो वर्किंग आवर 8 से 9 घंटे का होता है। इस तरह लोग हर हफ्ते 45 से 48 घंटे काम करते हैं। हालांकि, कुछ कंपनियों में लोगों को वर्किंग आवर के बाद भी काम करना पड़ता है। इसकी वजह से ना सिर्फ उनकी शारीरिक स्थिति पर असर पड़ता है, बल्कि काम के दबाव शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों के साथ-साथ बड़े-बड़े डॉक्टरों ने भी सरकार को चेताया है। डॉक्टरों की मानें तो भारत में ओवरवर्क का ट्रेंड बेहद कॉमन है।

भारत में वैसे तो वर्किंग आवर 8 से 9 घंटे का होता है। इस तरह लोग हर हफ्ते 45 से 48 घंटे काम करते हैं। हालांकि, कुछ कंपनियों में लोगों को वर्किंग आवर के बाद भी काम करना पड़ता है। इसकी वजह से ना सिर्फ उनकी शारीरिक स्थिति पर असर पड़ता है, बल्कि काम के दबाव शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों के साथ-साथ बड़े-बड़े डॉक्टरों ने भी सरकार को चेताया है। डॉक्टरों की मानें तो भारत में ओवरवर्क का ट्रेंड बेहद कॉमन है।

भारत में वैसे तो वर्किंग आवर 8 से 9 घंटे का होता है। इस तरह लोग हर हफ्ते 45 से 48 घंटे काम करते हैं। हालांकि, कुछ कंपनियों में लोगों को वर्किंग आवर के बाद भी काम करना पड़ता है। इसकी वजह से ना सिर्फ उनकी शारीरिक स्थिति पर असर पड़ता है, बल्कि काम के दबाव शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों के साथ-साथ बड़े-बड़े डॉक्टरों ने भी सरकार को चेताया है। डॉक्टरों की मानें तो भारत में ओवरवर्क का ट्रेंड बेहद कॉमन है।

## ईवीएम संदिग्धता: या इलाही ये माजरा क्या है ?

हरियाणा विधानसभा चुनाव के अप्रत्याशित परिणामों ने पूरे देश के न केवल सभी प्रमुख एजेंसीज द्वारा किये गए एक्जिट पोल्स को बुरी तरह झुठला दिया बल्कि बड़े बड़े राजनैतिक विश्लेषकों को भी हैरानी में डाल दिया। मजे की बात तो यह कि केवल कांग्रेस पार्टी ही हरियाणा में सत्ता में वापसी की उमीदों को लेकर गदगद नहीं थी बल्कि स्वयं भाजपा भी यह एहसास था कि किसान आंदोलन,अग्निवीर योजना व पहलवानों जैसे ज्वलंत मुद्दे उठने के बाद राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में इनके अलावा भाजपा को दस वर्ष की सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी संभावना के तहत भाजपा ने लगभग 35 प्रतिशत वर्तमान विधायकों के टिकट काट दिए थे। टिकट कटने वालों में कई मंत्री भी शामिल थे। इस कवायद के बावजूद 12 में से 9 मंत्री चुनाव में पराजित हो गये। हद तो यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा की सीटों को भी बदल दिया गया था। इन सबके बावजूद नायब सैनी और अनिल विज जैसे नेताओं को भी मामूली मतों से ही जीत हासिल हुई। राज्य में 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां बीजेपी की जीत का अंतर 5 हजार से भी कम है। आठ अक्टूबर को जब सुबह मतगणना शुरू हुई उस समय एग्जिट पोल द्वारा घोषित पूर्वानुमानों के अनुरूप ही कांग्रेस की भारी जीत के रुझान सामने आने लगे। बताया गया कि बैलट पेपर की गिनती में कांग्रेस तेजी से आगे जा रही थी परन्तु जैसे ही ई वी एम के मतों की गिनती शुरू हुई आंकड़ों ने उसी तेजी से करवट लेना शुरू कर दिया। उसी समय पूरे देश के सोशल मीडिया पर यह संदेह जाहिर किया जाने लगा कि क्या भाजपा द्वारा फिर श्खेला २ कर दिया गया ? और शाम होते होते भाजपा राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 48 पर जीत दर्ज करने व जरूरी बहुमत हासिल करने की ओर बढ़ चली। जबकि एक्जिट पोल के अनुसार 50 से 65 सीटें जीतने की उम्मीद रखने वाली कांग्रेस को मात्र 37 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। इन चुनाव परिणामों ने निश्चित रूप से सभी को हैरान इसलिये भी कर दिया क्योंकि राज्य से भाजपा की हरियाणा में सत्ता से बिदाई की रिपोर्ट्स केवल मीडिया आधारित नहीं थी बल्कि स्वयं अनेक सरकारी एजेंसीज ने भी यही फीड बैक दिया था। इसीलिये भाजपा के पक्ष में आये इन अप्रत्याशित परिणामों को लेकर संदेह पैदा होना स्वभाविक भी था। और इस्तरह निशाने पर एक बार फिर ई वी एम आ गयी। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया कि हरियाणा चुनाव में कई जगह ई वी एम को हैक किया गया है। यह सवाल भी उठा कि अनेक ई वी एम इंडिकेटर में बैटरी की मात्रा 90 व 95 : तक दिखा रही थी जबकि मतदान के अंतिम समय में प्रायः ई वी एम की बैटरी चार्जिंग की मात्रा 60 से 70: के बीच या इससे भी कम ही हुआ करती है। कांग्रेस का आरोप है कि जहां जहां ई वी एम में बैटरी कम थी उनमें प्रायः कांग्रेस को बढ़त मिली है। इस आरोप का सीधा अर्थ है कि ई वी एम को बदल दिया गया। कांग्रेस द्वारा 20 सीटों पर इस्तरह की गड़बड़ी होने की शिकायत दर्ज की गई है। सवाल यह है कि जब राहुल गांधी ने 17 मार्च को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के समय मुंबई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि राजा की आत्मा ईवीएम में है, उस समय केवल राहुल गांधी ही नहीं बल्कि एम के स्टालिन व फारूक अब्दुल्ला जैसे अनेक बड़े नेताओं ने भी ईवीएम का मुद्दा उठाया था। और उस समय सभी का ई वी एम को लेकर एक ही स्वर था कि यदि उनकी सरकार आएगी तो वे ईवीएम को हटा देंगे। सवाल यह है कि आज जबकि हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर विधान सभा के भी चुनाव परिणाम आये हैं। और जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉफरेंस व कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला जबकि हरियाणा में भाजपा को जीत मिली। ऐसे में यदि कांग्रेस के नेता हरियाणा में ई वी एम की कार्यप्रणाली में त्रुटियां निकाल रहे हैं तो फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा परिणामों से सहमत क्यों ? पिछले लोकसभा चुनावों में इण्डिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश व हरियाणा में भी अच्छा प्रदर्शन रहा। उस समय भी किसी ने ई वी एम पर इतना दोष नहीं मढ़ा। कर्नाटक में जीते तो भी ई वी एम ठीक थी? और इन सबसे बड़ी बात यह कि जब विपक्षी दलों के नेता ई वी एम को ही गलत बताते हैं फिर आखिर अब तक पूरे विपक्ष ने मिलकर ई वी एम के विरुद्ध संयुक्त रूप से कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं किया ? यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के कई वरिष्ठ वकीलों व सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा चलाये जा रहे ई वी एम विरोधी आंदोलन का भी किसी राजनैतिक दल ने खुलकर साथ नहीं दिया ? यदि वास्तव में ई वी एम निष्पक्ष चुनाव प्रभावित करने की क्षमता रखती है तो निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के लिये घातक है। सभी राजनैतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध करना चाहिये। यहाँ तक कि यदि सत्ता पक्ष के भी कई वरिष्ठ नेता,तकनीकी एक्सपर्ट और पूरा विपक्ष ई वी एम से चुनाव नहीं चाहता तो इसके द्वारा होने वाले चुनावों का बहिष्कार तक किया जाना चाहिये। क्योंकि सच तो यह है कि ई वी एम पर शुरुआती संदेह की ऊँगली तो भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी व सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा ही उठाई गयी थी। वैसे भी इसकी संदिग्धता को लेकर इसलिये भी सवाल उठते रहते हैं कि आखिर दुनिया के अनेक आधुनिक देशों ने इसका प्रचलन अपने देशों में क्यों बंद कर दिया ? और आधुनिक होने के बावजूद ऐसे देशों में आज भी चुनाव बैलट पेपर द्वारा ही क्यों कराये जाते हैं ? ई वी एम की संदिग्धता को लेकर स्थिति स्पष्ट,पारदर्शी व सर्वस्वीकार्य होनी चाहिये। बेईमानी पर आधारित लोकतंत्र वास्तविक लोकतंत्र का परिचायक नहीं हो सकता।

# राजर्षि टंडन में यूजी-पीजी में दाखिले के लिए दो दिन का मौका, पीएचडी में भी प्रवेश शुरु

वाराणसी। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में यूजी-पीजी में दाखिले के लिए अभ्यर्थियों के पास दो दिन का और मौका है। बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ एमए, एमएससी सहित अन्य पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थी 15 अक्टूबर तक दाखिला ले सकते हैं। विश्वविद्यालय में शोध करने के लिए 26 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी से जुड़े वाराणसी समेत सात जिलों (वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली और सोनभद्र) में करीब 250 अ्ययन केंद्र हैं। इसमें करीब 13 हजार विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। क्षेत्रीय

समन्वयक डॉ. एसके सिंह का कहना है कि यूजी-पीजी के साथ ही फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल में डिप्लोमा व डिग्री आदि पाठ्यक्रमों में 15 अक्टूबर तक प्रवेश लिया जा सकता है। विश्वविद्यालय में शोध के लिए 26 अक्टूबर तक बिना बिलंब शुल्क जबकि बिलंब शुल्क के साथ छह नवंबर तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। समन्वयक ने बताया कि शोध में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 23 नवंबर को प्रस्तावित है।

प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि कल तक कुलपति प्रो. सत्यकाम जी ने प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक कर दी गई है। विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीलिब विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। क्षेत्रीय



एमबीए, एमसीए और एकल विषय में स्नातक डिग्री, पर्यटन और फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल में डिप्लोमा आदि पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर कर दी गई है। पीएचडी में भी प्रवेश प्रारंभ हुआ

एक अक्टूबर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। 14 विभिन्न विषयों में पीएचडी के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर है। विलंब शुल्क के साथ 6 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है।

## फंदे से लटका मिला एमबीबीएस छात्र का शव

सफेदाबाद (बाराबंकी)। हिंद मेडिकल कॉलेज सफेदाबाद में एमबीबीएस के एक छात्रा का शव हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला। वह वाराणसी जिले के एक चिकित्सक का पुत्र था। शुरुआती जांच में पता लगा कि उपस्थिति कम होने के चलते वह फेल होने के डर से खिंचित रहता था। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर चले गए। वाराणसी जिले के थाना बड़ागांव क्षेत्र के सिधालपुर निवासी विकास प्रसाद यादव (26) हिंद मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष का छात्र था। वह कॉलेज परिसर में ही बने हॉस्टल के कमरे में एमबीबीएस के छात्र मनीष कुमार के साथ रहता था। पुलिस के अनुसार शुक्रवार रात करीब नौ बजे मनीष खाना खाने मेंस गया था। कुछ देर बाद लौटा तो कमरे का

दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी पुकारने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो स्टॉफ व अन्य छात्र आ गए। दरवाजा तोड़कर सभी अंदर पहुंचे तो बेडशीट के फंदे के सहारे विकास का शव लटक रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की मगर कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। सूचना मिलने के बाद रात करीब तीन बजे वाराणसी से पिता डॉ. ओमप्रकाश यादव व अन्य परिजन पहुंच गए। छात्रों का कहना था कि कॉलेज में विकास की उपस्थिति कम होने से वह डिप्रेशन में था। हो सकता है इसी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली हो। परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। शहर कोतवाल अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस आत्महत्या का कारण स्पष्ट करने में जुटी है।

## काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन शुरू, बदलेगी जलधरी की डिजाइन, गर्भगृह में एक-एक को मिलेगा प्रवेश

वाराणसी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पांच दिनों के बाद स्पर्श दर्शन शुरू हो गया। सख्त नियमों के साथ ही दर्शन की व्यवस्था को शुरु किया गया है। स्पर्श दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को एक-एक करके गर्भगृह में प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही मंदिर में तैनात सुरक्षाकर्मियों की हर दो घंटे पर ड्यूटी बदलेगी। मंदिर प्रशासन ने दर्शन पूजन की व्यवस्थाओं में कई बदलाव किए हैं। गर्भगृह में दर्शन पूजन के दौरान अब नियमित रूप से डेढ़ फीट का अरघा लगाकर ही आम श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही झांकी दर्शन के दौरान लगाने वाली जलधरी की डिजाइन में भी बदलाव किया जा रहा है। अब मंदिर में स्थायी जलधरी लगाई जाएगी ताकि उसे बार-बार निकालने और लगाने की जरूरत



नहीं होगी। सात अक्टूबर को मंदिर में स्पर्श दर्शन के दौरान दो श्रद्धालुओं के अरधे में गिरने की घटना के बाद मंदिर प्रशासन ने यह बदलाव किया है।मंडलायुक्त कोशल राज शर्मा ने बताया कि गर्भगृह में ड्यूटी करने वाले सुरक्षाकर्मियों का ड्यूटी रोस्टर घटना की पुनरावृत्ति भी नहीं होगी।

श्रद्धालुओं को एक-एक करके ही प्रवेश करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही गर्भगृह में नियमित रूप से अरघा लगाकर ही स्पर्श दर्शन कराया जाएगा। डेढ़ फीट का अरघा लगने से बाबा विश्वनाथ के विग्रह की भी सुखा होगी और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति भी नहीं होगी।

## दिनदहाड़े चोरों ने 15 लाख के गहने-नकदी उड़ाए

चहनिया। बलुआ थाना क्षेत्र के चहनिया कस्बा में बानेश्वर मजूमदार के घर चोरों ने रविवार को दिनदहाड़े इल्मीनान से मंदिर में रखे आलमारी से करीब 15 लाख रुपये के गहने व 40 हजार रुपये लेकर फरार हो गये। परिजन आलमारी से सामान निकालने लगे तो गहने गायब देख सन्न रह गये। पुलिस इसकी जांच पड़ताल में लगी है। चहनिया कस्बा के रहने वाले बानेश्वर मजूमदार कस्बा में ही मेडिकल स्टोर चलाते हैं। प्रतिदिन की भांति वे अपने बच्चों के साथ मेडिकल स्टोर पर चले गये। उनकी पत्नी घर में रहती हैं जो घर का दरवाजा चिपका कर बगल में कहीं चली गयीं। चोरों ने घर में घुसकर मन्दिर में रखे आलमारी को खोलकर बगल के दर्राज में रखा दो सोने के हार, सोने की अंगूठी,चार जोड़ी सोने का बाली झुमका, एक सोने का मंगलचूत्र व 40 हजार रुपये नकद चुरा ले गये।

## इमिलियाडीह में फोरलेन के किनारे बनेगा रोडवेज बस स्टेशन, भेजा प्रस्ताव

वाराणसी। रोडवेज बस स्टेशन को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की कवायद तेज हो गई है। नौ अक्टूबर को प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग और शासन की अध्यक्षता में बैठक के बाद प्रस्ताव के लिए एआरएम और जमीन उपलब्ध कराने के लिए अपर जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया था। मऊ डिपो के एआरएम ने नगर के इमिलियाडीह में गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन के किनारे जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव अपर जिलाधिकारी को भेजा है। बस स्टेशन को स्थानांतरित करने का उद्देश्य शहर की चार लाख से अधिक की आबादी को वायु प्रदूषण और जाम से मुक्ति दिलाना है। शासन की तरफ से जनवरी में भी करीब सात एकड़ जमीन तलाशने के लिए पत्र भेजा गया था। इसके लिए जमीन निशुल्क चाहिए जो प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। वर्तमान में मऊ डिपो की 58 रोडवेज बसों सहित गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, आज़मगढ़, प्रयागराज परिक्षेत्र सहित प्रदेश की अन्य डिपो से रोजाना 400 से अधिक बसों का ठहराव रोडवेज परिसर में होता है। शहर के बीचोबीच और जगह कम होने के चलते रोजाना शहरवासियों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। वहीं बस के चालकों द्वारा रोडवेज परिसर के बाहर मुख्य सड़क पर यात्रियों को बैठाने से समस्या और बढ़ जाती है। फोरलेन के किनारे बस स्टेशन बन जाने से बसें अपने निर्धारित समय से गंतव्य तक पहुंचेंगी। ऑटो, ई-रिक्शा और अन्य सवारी वाहनों की आय बढ़ेगी। शासन से पत्र मिलने के बाद नगर के इमिलियाडीह में फोरलेन के किनारे जमीन उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। जनवरी में भी पत्र भेजा गया था। जमीन मिलने पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। -हरिशंकर पांडेय, एआरएम, मऊ

## 65 फीट ऊंचा रावण का पुतला दहन, लगे जय-जय श्रीराम के जयकारे

अलीगढ़ (यूएनएस)। विजयदशमी का पर्व शनिवार को अलीगढ़ में धूमधाम से मनाया गया। श्रीरामलीला गौशाला सेवा समिति के तत्वावधान में हर साल की तरह इस बार भी नुमाइश मैदान में विजयदशमी पर्व का आयोजन किया गया। जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया गया। उत्सव के दौरान बुराई का प्रतीक माने जाने वाले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। रावण का पुतला इस बार 65 फुट का बनाया गया था। वहीं वहीं कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले 55-55 फुट के तैयार किए गए हैं। बुराई का प्रतीक माने जाने वाले इन पुतलों का श्रीराम और लक्ष्मण ने शनिवार को दहन किया। नुमाइश मैदान पर उत्सव से पहले रामलीला मैदान से भगवान श्रीराम के सिंहासन और मां काली की शोभायात्रा निकाली गई। इसमें 55 से ज्यादा डोले शामिल हुए थे। जिसमें श्रीराम, लक्ष्मण, वीर हनुमान, रावण समेत अन्य लोगों के डोले शामिल होंगे। शोभायात्रा दोपहर 1 बजे शुरू होगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। रामलीला मैदान से शुरू होकर यह शोभायात्रा आर्यसमाज रोड, मदारगेट चौराहा, गांधीपार्क चौराहा, मामूभांजा होते हुए मीरूमल चौराहा पहुंची। श्रीराममोहन मन्दिर से श्रीकाली सवारी मुहल्ले में भ्रमण के बाद शोभायात्रा में सम्मिलित हुई। फिर शोभायात्रा बारहद्वारी चौराहा, रघुवीरपुरी चौराहा, नई तहसील के सामने होते हुए शाम 7 बजे नुमाइश मैदान पहुंची। यहां पर श्रीराम और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध का मंचन किया गया। जिसके बाद श्रीराम के हाथों रावण वध की लीला हुई। लंका पर विजय और रावण के वध के बाद श्रीराम, लक्ष्मण, सीता आदि के डोले मसूदाबाद जीटी रोड होते हुए वापस रामलीला मैदान अचलरत्नाल पहुंचे। डोला यात्रा में लगभग 70-80 झांकी शामिल रही, जो आकर्षण का केंद्र बनी रही। आयोजकों ने बताया कि प्रभुराम के लिए विशेष रथ का निर्माण किया गया। सात आदिर्तिक्रियल घोड़ों वाले रथ पर प्रभु राम सवार होकर युद्ध क्षेत्र में पहुंचे थे। वहीं रावण पांच घोड़ों वाले रथ पर आया। इसके अलावा गणेशजी की झांकी, राधा कृष्ण, हनुमानजी, शिव की झांकी, काली झांकी समेत लगभग 100 झांकियां शामिल हुए। उत्सव के दौरान रामलीला कमेटी के साथ ही मेयर प्रधांत सिंधल, डीएम विशाख जी., एसएसपी संजीव सुमन, एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट, एसपी सिटी मृगांग शेखर पाठक, एसपी देहात अमृत जैन, एसपी मयंक पाठक समेत जिले के विभिन्न आलाधिकारी और मेला कमेटी के पदाधिकारी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे।

## मुंबई से माता सीता पर टिप्पणी, गाजीपुर में मुकदमा

वाराणसी। सोशल मीडिया पर दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति ने सीता माता को लेकर गलत टिप्पणी कर दी। इसे लेकर एक्स पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। दीपक शर्मा नाम के एक यूजर ने पोस्ट करके दिलदारनगर निवासी मोहम्मद फयाज पर गाजीपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। साथ ही अपने पोस्ट को गाजीपुर पुलिस को भी टैग कर दिया। इस संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने जांच की तो आरोपी दिलदारनगर थाना क्षेत्र के घनाडी गांव का निकला। उसकी उम्र 22 वर्ष है। वो वर्तमान में मुंबई में रहकर प्राइवेट नौकरी करता है। मुंबई में होने के कारण मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को बुलाने के लिए उसके परिजनों को कहा है। एसपी डॉ. ईरज राजा ने कहा कि मामला संज्ञान में आते ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपी मुंबई में है।

## जून में नेट क्वालिफाई करने वालों को ही पीएचडी में मिलेगा एडमिशन, पोर्टल पर नोटिफिकेशन जारी

वाराणसी। जून 2024 में नेट परीक्षा पास किए उम्मीदवारों को ही बीएचयू के 2024-25 सत्र के पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा। यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट के अलावा किसी भी दूसरी प्रक्रिया से पीएचडी में प्रवेश नहीं मिलेगा। बीएचयू ने एडमिशन पोर्टल पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 27 मार्च 2024 को यूजीसी की सार्वजनिक अधिसूचना के आधार पर, सत्र 2024-25 में नेट परीक्षा के स्कोर पर ही एडमिशन होगा। इसमें, जून 2024 में नेट-यूजीसी में मिले मार्क्स ही काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा, विश्वविद्यालय की ओर से इस सत्र के लिए कोई अलग शोध प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। अब नेट एग्जाम के 70 प्रतिशत अंक जुड़ेंगे



कई छात्रों ने बीएचयू के इफेंसले का सोशल मीडिया पर विरोध किया है। कहा कि बीएचयू ने करीब चार महीने पहले नया पीएचडी ऑर्डिनेंस जारी किया है, जिसमें ये भी नियम लाया गया था। छात्रों ने बताया कि पीएचडी के लिए बीएचयू अपना भी एंट्रेंस कराता था। जो स्टूडेंट्स यूजीसी-नेट की परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाते, वे आरईटी (रिसर्च एंट्रेस टेस्ट) एग्जाम के जरिए ही पीएचडी में प्रवेश पाते थे। अब 70 प्रतिशत मार्क्स नेट एग्जाम के और 30 प्रतिशत इंटरन्यू के नंबर जोड़कर आकलन किया जाएगा।

जिससे कार अचानक सड़क किनारे खड़ी बालू लदे ट्रैलर से टकरा गई कार का अमला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। डीह तिलक ठाकुर क्षेत्र में नौ महीने में सात घटनाएं मऊ से बलिया जाने वाले मार्ग पर हलधरपुर थाना के डीह तिलक गांव के पास कई हादसे हो चुके हैं। जिसमें कई लोग घायल हुए तो कुछ ने जान गंवाई। बीते नौ महीने में यहां पर सात घटना हो चुकी हैं। एक बार फिर बड़ी घटना होने से यह स्थान चर्चा का विषय बना रहा है। लोगों का कहना है यहां पर न तो कोई मोड़ है और न ही कोई ऐसी जगह जो हादसे का कारण हो, लेकिन अक्सर यहां होने वाले हादसे लोगों को भयभीत करते हैं।

## इनोवेशन, स्टार्टअप और आदिवासी विकास के लिए काशी विद्यापीठ ने किया समझौता

वाराणसी। स्टार्टअप, इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए महान्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने बिहार के बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। दोनों विश्वविद्यालय आपस में संयुक्त रिसर्च करारेंगे। संसाधनों को साझा करने के साथ ही आदिवासियों के विकास और पर्यावरण से जुड़े कामों को बढ़ावा दिया जाएगा। यूजी, पीजी और पीएचडी कोर्स भी शुरू होंगे। मुजफ्फरपुर स्थित बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय से आए कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र राय और विद्यापीठ के कुलपति प्रो. आनंद कुमार प्यागी ने रविवार को अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किया। ये समझौता पूरे पांच साल तक चलेगा। प्रोफेसरों और छात्रों के बीच संयुक्त रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप कराने के साथ ही दोनों विश्वविद्यालय अपने-अपने रिसर्च और तकनीक भी एक-दूसरे से साझा करेंगे। शिक्षकों और विद्यार्थियों का एक्सचेंज कार्यक्रम और संयुक्त फ़ैकल्टी डेवलपमेंट भी होगा। दोनों कुलपति ने कहा कि इससे यूपी और बिहार के छात्र-छात्राओं को काफी फायदा पहुंचने वाला है। छोटे और कुटीर उद्योग को लेकर भी दोनों संस्थान अपने-अनुभव साझा करेंगे।

## ओवरटेक करने के चक्कर में कार गुसी दुकान में, बालक की मौत

सेवापुरी। कपसेटी बाजार में शनिवार की रात भदोही की तरफ से आ रही कार को ओवरटेक करने के चक्कर में एक अन्य कार उससे टकरा गई। इसके बाद कार ने साइकिल स्टोर को क्षतिग्रस्त करते हुए फूल-माला की दुकान पर खड़े एक बालक को कुचल दिया। घटना से गुरसाए ग्रामीणों ने वाराणसी-भदोही मार्ग पर जाम लगा दिया। कपसेटी, जंसा, राजातालाब और मिर्जामुराद थाने की पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ प्रभावी तरीके से कारवाई का आश्वासन देकर जाम लगाए हुए लोगों को शांत कराया। भदोही से वाराणसी की तरफ जा रही कार को एक अन्य कार ओवरटेक करने के चक्कर में अनियंत्रित होकर उससे टकरा गई। इसके बाद वह कार एक साइकिल स्टोर में जा घुसी। तीन ट्रॉली और सात साइकिल को क्षतिग्रस्त करने के बाद कार ने पास में ही मौजूद रमेश मोदनवाल को फूल-माला की दुकान पर खड़े 13 वर्षीय प्रिंस मोदनवाल को कुचल दिया। हादसे में प्रिंस की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची कपसेटी थाने की पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया। उधर, प्रिंस के परिजनों ने बताया कि वह हादसे से लगभग 20 मिनट पहले दुर्गा प्रतिमा विसर्जित कर लौटा था और फूल-माला की दुकान पर खड़ा हो गया था। प्रिंस दो भाई और एक बहन में सबसे बड़ा था।

## न्यू होटल इंटरनेशनल के पार्टनरशिप को लेकर विवाद, मुकदमा

वाराणसी। लहुराबीर स्थित न्यू इंटरनेशनल होटल की पार्टनरशिप का विवाद गहरा गया है। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना के वीवीटी रोड, गोपालपुर की निवासिनी और लहुराबीर वार्ड में रहने वाली सुमन दूबे ने अपने देवर लखनऊ के अलीगंज के मूल निवासी व गोआ में रहने वाले वीरेंद्र दूबे के खिलाफ चेतगंज थाने में धोखाधड़ी सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया है। सुमन ने बताया कि उनके पति व उनके तीन भाई व उनकी मां न्यू इंटरनेशनल होटल का व्यवसाय पार्टनरशिप में शुरू किए थे। उनके पति की मौत के बाद उन्हें पार्टनर बनाया गया। वह कोलकाता में रहती थी, इसलिए वीरेंद्र कुमार दूबे होटल का व्यवसाय देखते थे। शुरू में उन्हें होटल से पैसा दिया गया। बाद में कई वर्षों से उन्हें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। वीरेंद्र कुमार दूबे से व्यवसाय का हिसाब-किताब व बैलेंस सीट देने को कहने पर वह जानमाल की धमकी देते हैं।

## तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत : संतोष

पीडीडीयू नगर। आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। भारत तेजी सेआगे बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, इसलिए पंडितों रच रहे हैं। ये बातें कैलाशपुरी स्थित पोद्दार भवन समागार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काशी प्रांत के शारीरिक प्रमुख संतोष ने स्वयंसेवकों के सम्मक्ष कही। कहा कि संघ के संस्थापकों ने विचार किया था कि स्वतंत्रता के पश्चात स्व का भाव जगेगा परंतु ऐसा नहीं हुआ। हम उसी स्व को जगाना चाहते हैं और इस कार्य को करने में हमारा तंत्र यानी हमारी शाखा का बड़ा महत्व है। हमारा मंत्र नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, काफ़ी कारगर है। इसका पारायण करते हुए आगामी वर्षों में एक सुखी, समृद्ध और प्रभावशाली भारत का निर्माण करने में सफल होंगे। इसके पूर्व विजयदशमी के दिन पथ संचलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यकर्ता पूर्ण गणेश में पोद्दार भवन के पास एकत्रित हुए और वहीं से नगर भ्रमण करने में संघपाल हुए पुनः पोद्दार भवन में आए जहां सभा संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में जिला कार्यक्रमक गुलाब सिंह, सह जिला संघचालक राम किशोर पोद्दार, डॉ अनिल यादव, शंभू नाथ गुप्ता, नगर कार्यवाह भुवनेश्वर, चंद्रेश्वर जायसवाल, नगर प्रचारक अंकित, हंसराज, संतोष, पार्थ, घनश्याम, रोहित आदि मौजूद रहे।

## 12 वर्षीय बालिका के साथ वृद्ध ने किया दुष्कर्म

चंदौली। सदर कोतवाली के एक गांव निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग से 12 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। बालिका गांव में चक्की पर गेहूं पिसाने गई थी। उसी दौरान बुजुर्ग ने उसके साथ हैवानियत की। आरोपित के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल जुट गई है। बताते हैं कि रोडवेज से सेवानिवृत्त 70 वर्षीय बुजुर्ग गांव में आटा चक्की चलाता है। 12 वर्षीय बालिका उसके यहां गेहूं पिसाने गई थी। उसी दौरान बुजुर्ग ने बालिका को अकेली देख कर उसको अपनी हवस का शिकार बनाया। उसके चुंगल से छूटकर किसी तरह बालिका अपने घर पहुंची। साथ ही घरवालों को आपबीती बताई। घटना की जानकारी होने के बाद परिजनों के साथ ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए।

## प्रेमी जोड़े की शादी के प्रमाणपत्र पर उठे सवाल, हाईकोर्ट ने SHO को दिए सत्यता की जांच करने का आदेश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएचओ कोतवाली प्रयागराज को शादीशुदा बताकर सुरक्षा मांगने आए याची जोड़े की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कहा है कि पता करें कि याची जोड़े की शादी किसने कराई, विवाह प्रमाणपत्र किस संस्था ने दिया, जिस पुरोहित ने शादी कराई उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करें। वहीं, याची जोड़े जांच में सहयोग न करें तो उन्हें अगली सुनवाई पर अदालत में पेश किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ ने शिवानी केसरवानी व एक अन्य की याचिका पर दिया है। प्रयागराज निवासी शिवानी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। उनका कहना था कि वे बालिग हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। विपक्षियों से उन्हें जान को खतरा है। इस पर कोर्ट ने एसएचओ कोतवाली से कथित शादी कराने वाली संस्था आर्य समाज चौक प्रयागराज के अध्यक्ष, सचिव व पुरोहित को 25 सितंबर को पेश करने का आदेश दिया था। आर्य समाज की ओर से अधिवक्ता आरबी मिश्र ने बताया कि कोर्ट में प्रस्तुत किया गया शादी का प्रमाणपत्र उनकी संस्था ने जारी नहीं किया है। वहीं, पुरोहित पंकज शुक्ल ने भी कहा कि उन्होंने याचियों की शादी नहीं कराई है और न ही विवाह प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किया है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए एसएचओ कोतवाली को याचियों से पूछताछ कर सच्चाई का पता लगाने का निर्देश दिया। अधिवक्ता आरबी मिश्र को न्यायमित्र नियुक्त कर अगली सुनवाई की तिथि 16 अक्टूबर को कोर्ट का सहयोग करने का आदेश दिया है।

## वाराणसी से कानपुर तक अपराधियों की जन्मकुंडली खंगाल रही जीआरपी

प्रयागराज। रेलवे ट्रैक को अवरूढ़ कर ट्रेनों को दुर्घटनाग्रस्त करने की साजिश रचने वालों की अब खैर नहीं है। जीआरपी ने वाराणसी से लेकर कानपुर तक रेलवे लाइन किनारे बस्तरियों व गांवों के अपराधियों व संदिग्धों की जन्मकुंडली तैयार करनी शुरू कर दी है। अब तक 596 लोग चिह्नित किए जा चुके हैं। अपराधियों व संदिग्धों के वर्तमान गतिविधियों की पूरी रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। ताकि ट्रेनों को दुर्घटनाग्रस्त करने की साजिश पर पूरी तरह लगाम लग सके। पिछले कुछ दिनों से रेलवे लाइन पर गैस सिलेंडर, भारी भरकम पत्थर, बिजली के खंभे व अन्य संदिग्ध वस्तुओं को रखकर ट्रेनों को दुर्घटनाग्रस्त करने के साजिश लगातार सामने आ रहे हैं।

उत्तर मध्य रेलवे				
ई-प्राण निविदा सूचना संख्या. 24/69 दिनांक: 08.10.2024				
भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रधान मुख्य सामग्री प्रबन्धक, 30म0रे0, प्रयागराज (आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणित इकाई) निम्नलिखित मर्दों के लिए ई-प्राण निविदाएं आमंत्रित करते हैं।				
क्र. सं.	निविदा संख्या	संक्षिप्त विवरण	मात्रा	निविदा खुलने की तिथि
1	70245014	ट्रान्स्फार्मर ऑइल	65,800 लीटर	13.11.2024
2	50245402	जेनेरी रिफिल 6 क्वार्टेड केबल्स	1544.5 किमी.	04.11.2024
3	50245453	सप्लाय ऑफ 12 कोर सिग्नलिंग केबल	5003.85 किमी.	11.11.2024
4	302242037	प्रेसर गेज 80x10 एमएम	362 नग	06.11.2024

उत्तर मध्य रेलवे	
दिनांक: 09.10.2024	
ई-निविदा सूचना	
उप मुख्य बिजली इंजीनियर/मति शक्ति यूनिट/30म0रे0/प्रयागराज, द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से निम्न कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है।	
निविदा सं.:	वि0-गडवाण/कार्य 05का-57-2024
कार्य का विवरण:	30म0 रेलवे के प्रयागराज मण्डल में पनकी धाम - GMC के मध्य 4 <sup>th</sup> लाइन के निर्माण के कारण नए 25 केवी0 एस.एस.बी. का प्रावधान।
अनुमानित लागत:	रु. 16271061.30
बिड सुरक्षा राशि:	रु. 231400.00
निविदा बन्द होने की तिथि तथा समय:	01.11.2024, 14:00 बजे
बोली प्रणाली:	एक पैकेट
निविदा खुलने की तिथि तथा समय:	01.11.2024, 15:00 बजे
कार्य अवधि:	04 महीना
नोटः (1) उपरोक्त ई-निविदा का पूर्ण विवरण (निविदा प्रश्न सहित) वेबसाइट <a href="http://www.ireps.gov.in">www.ireps.gov.in</a> पर निविदा खोलने की तिथि से 21 दिन पहले से उपलब्ध होगा। (2) उपरोक्त निविदा में ई-बिड के अलावा किसी अन्य रूप में बिड स्वीकार नहीं की जायेगी। इस प्रयोजन हेतु वेबद्वारा को चाहिए कि वे अपने आपको डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ IREPS की वेबसाइट पर पंजीकृत करावें। (3) किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान के लिए IREPS की वेबसाइट की हेल्प लाइन से सम्पर्क किया जा सकता है।	
1784/24 (ADM)	
North central railways   <a href="http://www.ncr.indianrailways.gov.in">www.ncr.indianrailways.gov.in</a>   @CPRONCR	

उत्तर मध्य रेलवे	
दिनांक: 09.10.2024	
ई-निविदा आमंत्रण सूचना	
भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य अभियन्ता-1/जी.एस.यू./प्रयागराज, उत्तर मध्य रेलवे के अधीन निम्नलिखित निर्माण कार्यों हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं (द्वारा खुली निविदा-एकल पैकेट प्रणाली एवं संयुक्त उद्यम/संघ/एमओओयू/एडस, अनुपयुक्त) समाप्ति की तिथि/समय, 01.11.2024, 15:00 बजे तक। बोली लगाने वाले अपने मूल/संशोधित बिड्स समाप्ति तिथि एवं समय तक मात्र जमा कर सकते हैं। इस निविदा के लिए मैन्युअल ऑफर की अनुमति नहीं है और प्राप्त किसी ऐसे मैन्युअल प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।	
निविदा संख्या :	DYCE-II-GSU-PRYJ-12-2024
अनुमानित लागत:	रु. 4.98 करोड़
कार्य का विवरण:	उप मुख्य अभियन्ता -1/ जी.एस.यू./प्रयागराज के अन्तर्गत प्रयागराज मंडल के 03 स्टेशन अवरक्षार, इकटिल और फुडूद स्टेशन पर गुरुस शेंड के प्रावधान के संबंध में पी-वे कार्य
घरोहर राशि:	रु. 3,98,800/-
कार्य समापन अवधि:	10 महीने
निविदा संख्या :	DYCE-II-GSU-PRYJ-13-2024
अनुमानित लागत:	रु. 2.63 करोड़
कार्य का विवरण:	सोनभद्र स्टेशन पर 01 अतिरिक्त गुरुस लाइन का प्रावधान
घरोहर राशि:	रु. 2,81,500/-
कार्य समापन अवधि:	08 महीने
सभी निविदा फार्म का मूल्य:	0.00/-
सभी निविदाएं खुलने की तिथि:	01.11.2024, 15:00
पात्रता मानदंड के लिए कार्य की समान प्रकृति की परिभाषा:	कोई पी0वे0 कार्य।
नोट - पूर्ण विवरण और निविदा जमा करने के लिए कृपया भारतीय रेलवे की <a href="http://https://www.ireps.gov.in">https://www.ireps.gov.in</a> वेबसाइट देखें। नोट:- उपरोक्त ई-निविदा का पूर्ण विवरण (निविदा प्रश्न सहित) <a href="http://https://www.ireps.gov.in">https://www.ireps.gov.in</a> पर निविदा तिथि तक 15:00 बजे तक उपलब्ध रहेगा। 2. उपरोक्त सभी निविदाओं में ई-बिड के अलावा किसी अन्य रूप से बिड स्वीकार नहीं की जायेगी। इस प्रयोजन हेतु वेबद्वारा को चाहिए कि वे अपने आपको I.T. Act - 2000 के अन्तर्गत CCA द्वारा जारी Class-III, Digital हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र के साथ IREPS की वेबसाइट पर पंजीकृत करावें। 3. निविदा के लिए मैन्युअल डिजिटल हस्ताक्षरित फाइलें/सिगल रेट पेज पर ही विचारणीय है। दूर तथा अन्य वित्तीय प्रमाण अन्य किसी भी फार्म/लेटरहेड पर यदि संलग्न है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा तथा सीपी तौर पर अमान्य कर दिया जायेगा। 4. संलग्न किये जाने वाले सभी प्रश्न निविदाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिये। 5. किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान के लिए IREPS की वेबसाइट की हेल्पलाइन से सम्पर्क किया जा सकता है।	
1786/24(DG)	
North central railways   @CPRONCR   <a href="http://www.ncr.indianrailways.gov.in">www.ncr.indianrailways.gov.in</a>	

# बहराइच दंगे पर बोलीं रीता जोशी, इसे रोकना होगा: प्रयागराज में पूर्व मंत्री ने कहा सभी को अपने धर्म का पालन करें, एक ईट दंगे में बदले ऐसा नहीं होना चाहिए

प्रयागराज। पूर्व मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने प्रयागराज में कहा कि बहराइच में दंगा दुखरूढ़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रीता जोशी ने कहा कि सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यूपी में कानून व्यवस्था सबसे बेहतर है। उन्होंने कहा कि एक ईट से दंगा हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। दंगे की साजिश वालों से होशियार रहना होगा। हिंदू धर्म के जुलूस हों हो या फिर मोहरम जुलूस शांति कायम रहनी चाहिए। रीता जोशी ने कहा कि स्व. कमला बहुगुणा के जन्म शताब्दी वर्ष में उनकी स्मृति में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। पूर्व सांसद प्रो. रीता बहुगुणा जोशी



ने बताया कि संस्कृति मंत्रालय उ. आदमकद कांस्य प्रतिमा बहुगुणा प्र. सरकार द्वारा कमला बहुगुणा की मार्केट न्याय मार्ग प्रयागराज में

## 12 साल के बच्चे को सांप ने डंसा: टीवी चालू करने गया था बच्चा, बोला- मां किसी ने काट लिया फिर बेहोश हुआ तो उठा ही नहीं



बालक चार बहनों में सबसे छोटा इकलौता भाई था। मौत की सूचना पर बहनें अंजलि, आंचल, आंशू, मीनाक्षी का रो-रो कर बुरा हाल हो गया है। मां किसी ने काट लिया फिर बेहोश हुआ तो उठा ही नहीं

प्रयागराज। प्रयागराज के फूलपुर में घर के कमरे में टेलीविजन चालू करने गए बच्चे को सांप ने डंस लिया। मां ने सोचा कि किसी चूहे या छछुंदर ने काटा होगा। कुछ देर बाद जब बच्चा बेहोश होने लगा तो परिजन फूलपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शहर के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल ले गए, वहां भी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के इफको पुलिस चौकी के चकमाली गांव निवासी अरविंद कुमार पटेल का 12 साल का इकलौता पुत्र आदित्य कुमार पटेल सुबह कमरे में टेलीविजन चालू करने गया था। कमरे की दीवार में बिल में बैठे जहरीले सांप ने डंस लिया। बच्चे ने मां सुशीला देवी को बताया तो मां ने सोचा किसी चूहे या छछुंदर ने काटा होगा। कुछ देर बाद बालक बेहोश होने लगा। परिजन शहर के स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल ले गए। वहां भी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजन बच्चे के जिंदा होने की उम्मीद में सोरांव झाड़ू-फूंक करने वाले के पास ले गए। वहां से भी मृतक होने की बात पर कुंडा प्रतापगढ़ में वैद्य के पास लेकर गये। वैद्य ने भी मृतक घोषित कर दिया। मृतक बालक के पिता दिल्ली में काम करते हैं। सूचना पर दिल्ली से रवाना हो लिए हैं। मृतक बालक के पिता दिल्ली में काम करते हैं। सूचना पर दिल्ली से रवाना हो लिए हैं। मृतक बालक के पिता दिल्ली में काम करते हैं। सूचना पर दिल्ली से रवाना हो लिए हैं।

## पूरब के आक्सफोर्ड से हो रहा छात्रों का मोहभंग: कोरोना के बाद सिर्फ पांच विदेशी छात्रों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लिया दाखिला

प्रयागराज। प्रयागराज में पूरब के आक्सफोर्ड के नाम से विख्यात इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिले को लेकर विदेशी छात्रों का मोह भंग होने लगा है। 2012 से 2023 के बीच 252 छात्र ही पंजीकृत रहे। इसमें स्नातक, परस्नातक और पीएचडी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी शामिल थे। लेकिन कोरोना महामारी की शुरुआत से अभी तक यानी तीन वर्षों की बात करें तो सिर्फ पांच विदेशी और एनआरआई छात्रों ने ही पढ़ाई के लिए पूरब के आक्सफोर्ड को चुना है। 2022-23 में एक भी विदेशी छात्र ने दाखिले के लिए आवेदन नहीं किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से सूचना के अधिकार के अर्न्तगत दी गई जानकारी के मुताबिक 2012 से 2023 में कोरोना काल के बाद सिर्फ पांच छात्रों ने ही प्रवेश लिया है। हालांकि इसके पहले विदेशी छात्रों की संख्या सैकड़ों में हुआ करती थी। अंतरराष्ट्रीय छात्रावास इन छात्रों से गुलजार होता था। विश्वविद्यालय में 2015-16 में सबसे अधिक 63 विदेशी छात्रों ने प्रवेश लिया था, लेकिन इसके बाद से विदेशी छात्रों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 2019-20 में यह संख्या 14 तक पहुंच गई। कोरोना काल के दौरान केवल पांच विदेशी छात्रों ने दाखिला लिया। 2023-24 में यह संख्या दो छात्रों तक सिमटकर रह गई। एनआरआई वाड/ स्पॉर्सड श्रेणी के छात्रों के लिए



आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई और आवेदन फार्म डाउनलोड कर 23 अक्टूबर रात 11.59 बजे तक आवेदन भेजा जा सकेगा।

## किशोरी को कार से अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म, बेहोश होने पर भाग निकले पांचों आरोपी



प्रयागराज। शंकरगढ़ में दुर्गा नवमी की आधी रात 17 वर्षीय किशोरी को घर के बाहर से कार में खींचकर दरिदगी की गई। परिजनों का आरोप है कि सामूहिक दुष्कर्म के बाद पांच आरोपी उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग निकले। पुलिस का कहना है कि किशोरी ने छेड़छाड़ की बात बताई है और संबंधित धारा में केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। किशोरी के पिता काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं जबकि उसकी मां चूड़ी-बिंदी व मैकअप का अन्य सामान बेचती हैं। 11 अक्टूबर की रात मां मेले में दुकान लगाने चली गई थी। घर में किशोरी व उसकी ममेरी बहन थी। मां ने बताया कि देर रात भतीजी ने फोन कर उसे जल्द घर आने को कहा। वह पहुंचती तो बताया कि रात ढाई बजे के करीब पड़ोस में रहने वाला शनि आया और दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही किशोरी ने दरवाजा खोला तो वह उसे अपने साले छोड़ व तीन अन्य लोगों की मदद से बलबल करके कार में खींच ले गया। मां का आरोप है कि खोजबीन करने पर बेटी भोर में शनि के घर के बाहर खड़ी कार में बेहोशी की हालत में मिली। सूचना देने पर डायल 112 पुलिस उसे पहले सीएचसी ले गई। वहां बेटी ने बताया कि शनि, छोटू ने अपने तीन अज्ञात साथियों संग मिलकर उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। फिर उसे कार में छोड़कर भाग निकले। जाते वक्त कहीं शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। मां का आरोप है कि पुलिस ने जबरन छोड़खानी की तहरीर पर उससे दस्तखत करा लिया। उधर पुलिस का कहना है कि किशोरी ने अस्पताल में अपने साथ छेड़छाड़ होने की बात बताई है। संबंधित धारा में केस दर्ज कर मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। परिजनों के मुताबिक, आरोपी ने पीड़िता के भाई का नाम लेकर दरवाजा खोलवाया था। ममेरी बहन ने बताया कि आरोपी शनि घर के बाहर पहुंचकर उसकी बुआ के बेटे का नाम लेकर आवाज लगा रहा था। यह सुनकर जब उसकी फुफेरी बहन दरवाजा खोलकर घर के बाहर निकली तो उसे कार में खींच ले जाया गया। उसकी चीख सुनकर वह भी पीछे गई लेकिन शनि ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उधर पीड़िता की मां ने बताया कि घर पहुंचने पर उसे दरवाजा बाहर से बंद मिला था।

## एक माह में दो बड़ी परीक्षाएं आयोग के लिए चुनौती, पीसीएस प्री और आरओ-एआरओ परीक्षा भी टलने के आसार

प्रयागराज। परीक्षा केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है, जिसके लिए 1076004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं, पीसीएस कोर्ट निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब सात एवं आठ दिसंबर को कराने की तैयारी में है